दैनिक नई दुनिया, भोपाल
28 OCT 2010

क्या शिवराज कर पाएंगे ऐसा ...?

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की संकल्पशक्ति अविश्वसनीय नहीं है, क्योंकि उन्होंने अब तक जो कहा है, वह कर के भी दिखाया है, किन्तु प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की होशंगाबाद बैठक के समापन अवसर पर जो भोपाल में वर्षों से जमें रसूखदार डॉक्टरों-प्रोफेसरों को हटाने और उनकी सिफारिश न करने की जो उन्होंने हिदायतें दीं, उससे एक आशंका पैदा हो गई है कि 'क्या शिवराज ऐसा कर पाएंगे?' इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे मुख्यमंत्रीजी की स्थिति उस 'रजिया' के समान है, जो 'गुंडन' में फंस गई है, इसलिए वे चाहकर भी कई जनहित के कार्य नहीं कर पा रहे हैं. अब बरसों से एक ही जगह पर कुंडलीमार कर बैठे रसूखदारों को छेड़ना वास्तव में उनकी 'बाम्बी' में हाथ डालने जैसा ही होगा और यदि विषपायी शिव यदि यह करने में सफल हो जाते हैं तो वे इस मायने में प्रदेश के प्रथम साहसी मुख्यमंत्री कहे जाएंगे? यह तो एक जग जाहिर तथ्य है कि भोपाल या राज्य के अन्य बड़े शहरों में कार्यरत अफसर से लेकर चपरासी तक ऊंची सिफारिश के आधार पर ही कई वर्षों से एक ही जगह जमें हुए हैं, जबकि बेचारे बिना सिफारिश वाले या निराश्रित अधिकारी-कर्मचारी अपनी नियुक्ति तिथि से ही गांवों की खाक छान रहे हैं। प्रदेश की राजधानी में तो और भी अलग नजारा है, यहां सिफारिश वाले नहीं रसूख वाले दादागिरी के साथ बरसों से जमें है और उन्हें हिलाने की कोई हिम्मत तक नहीं कर सकता, इनके अधिकांश तो वरिष्ठ अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की धर्म पत्नियां हैं, जो अपने आवास के निकट के शिक्षण संस्थान या कार्यालय में कार्यरत है। कुछ ही वर्ष पहले एक प्रसिद्ध कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा था कि वे अपने महाविद्यालय में अनुशासन इसलिए नहीं रखपाती क्योंकि भृत्या तक ऊंची सिफारिश वाली है इसलिए वे हर किसी से अनुनय-विनय करके ही कॉलेज चला रही है। यह राजधानी के सिर्फ एक कॉलेज की वास्तविक तस्वीर है, जबकि राजधानी के सभी कॉलेजों की कमीबेश यही स्थिति है, बरसों से यही हाल है राजधानी के, जबकि शासन का सख्त नियम है कि कोई भी शासकीय कर्मी तीन साल से अधिक एक ही स्थान पर सेवा नहीं कर सकता। किन्तु जब नियम-कानून बनाने वालों के परिजन ही इस नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं तो अन्यों का क्या कहें? यहीं नहीं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले यदि राजधानी से बाहर हो भी जाते हैं तो उनके सरकारी बंगले उनकी पत्नियां अपने नाम करवा लेती हैं जिससे कि जब भी 'साहब' राजधानी पधारें तो उन्हें आवास की समस्या न हो? राजधानी में कई तो ऐसे भी डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर मिल जाएंगे जो यहीं नियुक्त हुए और यहीं से सेवानिवृत भी हो गए उन्होंने भोपाल के बाहर का जीवन कैसा है? यह पूरे शासकीय सेवा काल में देखा ही नहीं? अब जब मुख्यमंत्री ने यह साहसिक संकल्प व्यक्त कर ही दिया है और वे यदि दृढ़ता पूर्वक उस पर अमल करते हैं तो प्रदेश में मुख्यमंत्री की मंशा और रसूखदारों के रसूख के बीच संघर्ष तेज होगा, फिर इसमें जीत किसकी होगी यह तो भविष्य के गर्भ में है, किन्तु यह सही है कि दो दिन पूर्व से जबसे मुख्यमंत्री ने अपना यह संकल्प व्यक्त किया है, तब से कई का दिन का चैन और रातों की नींद हराम हो गई है पूरे तंत्र में खलबली सी मच गई है, क्योंकि प्रदेश के अब तक के इतिहास में किसी भी मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर सख्त रुख कभी नहीं अपनाया जबकि यह रोग प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ सभी दूर व्याप्त है और राजधानी तो इस रोग की भी राजधानी बनी हुई है, इसलिए शिवराज जी को 'चैरिटी बिगिन्स फ्रॉम होम' की तर्ज पर अपने संकल्प को मूर्तरूप देने की शुरुआत राजधानी से ही करना चाहिए, इसलिए उन निराश्रित कर्मियों को एक आशा की किरण जरूर नजर आएगी जो बरसों से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं।